

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 44/2021

GCMS NO. : 2021/90

-: प्रार्थीगण :-

बनाम

-: अप्रार्थीगण :-

1. केसाराम पुत्र छोगा

2. पूसा पुत्र छोगा

3. जयपराम पुत्र छोगा

जाति- मेघवाल, निवासी- सिणला,
तहसील- जैतारण जिला- पाली
(राज.)

1. बीजाराम पुत्र रुघा

2. मांगीलाल पुत्र रुघा

3. झुमरराम पुत्र रुघा

4. धोकल पुत्र रुघा फौत के का.मु.

4.1 भगवानराम पुत्र धोकल

4.2 दिनेश पुत्र धोकल

4.3 मदनलाल पुत्र धोकल

4.4 शांति बेवा धोकल जातियान-
मेघवाल, निवासीगण- सिणला,
तहसील जैतारण जिला पाली।

5. तहसीलदार भूमिधारी राजस्थान
सरकार जैतारण जिला पाली।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपत्ति धारा 151 सीपीसी
तारीख रजु:-01.04.2021

उपस्थित:-

1. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

2. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-: निर्णय :-

दिनांक:- 28/07/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपत्ति धारा 151 सीपीसी, के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सिणला पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे खसरा नम्बर 475 वक्त सेटलमेन्ट से गै.मु. मगरी के रूप में राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है। परन्तु उक्त सम्पूर्ण खसरा गै.मु. मगरी नही होकर कुछ भू-भाग काबिल काश्त के है। जिस पर सायलान् के पिता छोगा व चुना व गैरसायलान् संख्या 1 से 4 के पिता रुघा व 4/1 से 4/4 के दादा व ससूर का वक्त सेटलमेन्ट से 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग था नकल गिरदावरी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। सायलान् व गैरसायलान् एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त भूमि मे सभी का सामलाती कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग था जो निम्न वंशावली से स्पष्ट है- प्रस्तुत वंशावली अनुसार सभी का खसरा नम्बर 475 रकबा 5-05 बीघा भूमि पर 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग था, नकल गिरदावरी साथ पेश है। यह है कि वक्त सेटलमेन्ट सेटलमेन्ट



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

कर्मचारियों द्वारा मौके पर बिना मौके की जांच किये बिना सायलान का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी में इन्द्राज नहीं कर केवल गैरसायलान के पिता कबा का नाम उसके 1/3 हिस्से अर्थात् 1.15 बीघा भूमि का नियमन/ आर्यटन कर राजस्व रेकर्ड में गैरखातेदार इन्द्राज कर दिया। जबकि वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक सायलान एवं गैरसायलान खसरा नम्बर 475 रकबा 5-05 बीघा भूमि में अपने अपने 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं व मौके पर सायलान व गैरसायलान के रहवासी मकान बने हुए हैं जिसमें मय परिवार के निवास करते हैं तथा इनके नाम का बिजली पाकी के बिल के कलेक्शन रूपा के नाम से लिये हुए है नकल बिजली बिल व पाकी बिल एवं रहवासी मकानात के फोटोग्राफर साथ पेश है। वादग्रस्त आराजी में सायलान का वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा काशत एवं उपयोग उपभोग है तथा अरसे दराज से सायलान के रहवासी मकान बने हुए है तथा कृषि उपयोग हेतु खुला कुआ (ओपन वेल) भी खुदा हुआ है जिसका सायलान व गैरसायलान सामलाती एवं संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करते हैं। सायलान वक्त सेटलमेन्ट से गिरफ्तार बिना किसी टेकटेक के शांतिपूर्वक उक्त भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काशतकार के करते चले आ रहे है। कानूनन पिछले 70 वर्षों से कब्जे काशत व उपयोग उपभोग से सायलान बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उक्त भूमि के खातेदार काशतकार हो चुके है। केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में सायलान का नाम इन्द्राज नहीं होने से घोषणा का वाद व यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। कानूनन जिन व्यक्तियों का वक्त सेटलमेन्ट व सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक पिछले 70 वर्षों से कब्जा काशत व उपयोग उपभोग नियमित कृषि भूमि पर है वह व्यक्ति बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उक्त भूमि का बतौर खातेदार काशतकार माना जावेगा व केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा नाम इन्द्राज नहीं करने से उसे उनके साम्पैतिक हक अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकेगा। इस कारण सायलान वादग्रस्त भूमि के पिछले 70 वर्षों से कब्जा काशत व उपयोग उपभोग से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काशतकार हो चुके है। इसलिए उनका नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने बाबत घोषणा का वाद व यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। सायलान के कब्जे काशत एवं उपयोग उपभोग बाबत गिरदावरी साथ पेश है। सायलान के पिता द्वारा व सायलान द्वारा समय समय पर गैरसायलान संख्या 5 के कार्यालय में व उनके अधीनस्थ कर्मचारी पट्टारी आदि को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये परन्तु गैरसायलान संख्या 5 ने आज दिन तक सायलान का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरा मद नहीं किया व दिनांक 05/03/2021 को सायलान ने गैरसायलान संख्या 5 के कार्यालय में खसरा नम्बर 475 रकबा 5-05 बीघा में से 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काशतकार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काशतकार के नाम इन्द्राज कर अमल दरा मद करने का निवेदन किया तब गैरसायलान संख्या 5 स्पष्ट रूप से इन्कार हुए व सायलान को बेदखल करने की



ग्रामपंच अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
त्रैतारण, त्रिला-पाली

धमकी दी व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का कथन किया। इस कारण से सायलान् के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। सायलान् का नाम राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज नहीं होने से गैरसायलान् आये दिन सीमा को लेकर वाद विवाद करते हैं व सायलान् को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जबकि गैरसायलान् को पूर्ण जानकारी है कि सायलान् 1/3, 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग है केवल मात्र राजस्व रेकॉर्ड में इनका नाम इन्द्राज नहीं है इनका फायद उठाते हुए गैरसायलान् सायलान् को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान् अपने मंसुबो मे कामयाब हो जाते है तो सायलान् को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हो पायेगी। इस कारण यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र विरुद्ध गैरसायलान् के पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं मौके पर सायलान् के कब्जे एवं उपयोग उपभोग से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायलान् के पक्ष मे प्रमाणित है यदि गैरसायलान् जोर जबरदस्ती अवैधानिक तरीके से सायलान् को कब् काश्त से बेदखल कर देते है एवं सायलान् के हक हिस्से की भूमि मे दखलन्दाजी करते है एवं खूर्द बुर्द कर कच्चा पक्का निर्माण करते है तो अपूर्णिय क्षति सायलान् को होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सभव नहीं होगी एवं सायलान् अपने जायज साम्पतिक हक अधिकारो से महरूम हो जायेगे तथा गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को सायलान् मौके पर विरोध करेगा तो लडाई झगडा टन्टा फसाद होगा जिससे विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी तथा पेचीदगिया बढेगी इसलिए इन तमाम परिस्थितियो मे सायलान् को अपने हक हिस्से की भूमि की सुरक्षा करने के लिये न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि सरहद मौजा सिणला पटवार हल्का डिगरना में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 475 वक्त सेटलमेन्ट मे गै.मु. मगरी के रूप मे राजस्व रेकॉर्ड मे इन्द्राज थी परन्तु उक्त आराजी का कुछ भाग जो काबिल काश्त होने से गैरसायलान् के पिता रुघाराम पुत्र गीगाराम को भूमिहीन होने से 1-15 बीघा जमीन आवंटन/नियमन हुई थी जबकि वादग्रस्त सम्पति मे सायलान् का कोई हक अधिकार नहीं है और नहीं उक्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी सम्पति है। नकल पासबुक नियमन/आवंटन की जबाब प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे जबाब प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि सायलान् एवं गैरसायलान् एक ही परिवार के सदस्य नहीं है सायलान् द्वारा जो वंशावली अंकित की है उसमे भी कईयो के नाम छोड दिये और खसरा



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला-राजस्थान

नम्बर 475 मे सायलान् का कोई हक अधिकार नहीं है। केवल जबाब देहन्दा जिनके पिता को 1-15 बीघा जमीन आवंटन हुई थी उस पर जबाब देहन्दा काबिज है शेष भू भाग पर सायलान् का न तो हक अधिकार है न ही कब्जा काशत है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि वादग्रस्त सम्पति मे सायलान् का कोई हक अधिकार नहीं है उक्त आराजी का रकबा बहुत बड़ा था जिसमे से जबाब देहन्दा के पिता उस समय भूमिहीन होने से जबाब देहन्दा के पिता को दिनांक 24/04/1976 को खसरा नम्बर 475 मे से 1-15 बीघा जमीन आवंटन/नियमन हुई थी और उस समय जबाब देहन्दा के पिता को गैरखातेदार के रूप मे उक्त आराजी आवंटन की थी और फिर लगातार जबाब देहन्दा के पिता का कब्जा काशत होने से 10 वर्ष बाद उन्हें खातेदारी अधिकार दिये गये थे तब से लेकर आज दिन तक जबाब देहन्दा अपने हक हिस्से की भूमि मे काबिज है। सायलान् का इस सम्पति मे कोई हक अधिकार नहीं है सायलान् ने जो 1/3, 1/3 हिस्सा अंकित किया है वह पूर्णतया गलत है क्योंकि वादग्रस्त सम्पति न तो पुश्तैनी है और न ही सायलान् का हक अधिकार है। सरकारी जमीन पर सायलान् को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य बेबुनियाद मनगढन्त होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 का जबाब है कि वादग्रस्त सम्पति पर सायलान् का कोई सेटलमेन्ट से हक अधिकार नहीं है न ही मौके पर सायलान् का कोई कब्जा काशत है और न ही वादग्रस्त सम्पति सायलान् एवं गैरसायलान् की सामलाती है उक्त सम्पति मे 1-15 बीघा जमीन पर एक मात्र मालिकाना जबाब देहन्दा का है। सायला का उक्त सम्पति में कभी न तो नाम इन्द्राज रहा है न ही उनका कब्जा रहा है। इस पद में जो सायलान् ने तथ्य अंकित किये वह केवल मात्र बनावटी तथ्य है। इसलिए जबाब देहन्दा अस्वीकार करता है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 का जबाब है कि वादग्रस्त सम्पति पर सायलान् का कोई कब्जा कारत नहीं है उक्त सम्पति एक मात्र जबाब देहन्दा के पिता को आवंटन हुई थी और उनका ही हक अधिकार है शेष जमीन सरकारी भूमि है जो सरकार के खाते में इन्द्राज है सायलान् का कोई 70 वर्षों से कब्जा कारत नहीं है और सरकारी भूमि में सायलान् कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है। इसलिए इस पद में वर्णित तथ्य जबाब देहन्दा अस्वीकार करते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 का जबाब है कि वादग्रस्त सम्पति जो कि जबाब देहन्दा के पिता को आवंटन हुई थी शेष आराजी की किस्म गै.मु. मगरी है और जो राजस्थान सरकार की जमीन है और जिसमे सायलान् का कोई हक अधिकार नहीं है और न ही गैरसायलान् संख्या 5 उनको कोई हक अधिकार दे सकता है और सायलान् द्वारा यह तथ्य अंकित करना कि 1/3 हिस्सा है वह पूर्णतया गलत अंकन किया है। वादग्रस्त सम्पति मे 1-15 बीघा जमीन जबाब देहन्दा के पिता को आवंटन हुई और उनके बाद उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए और आज भी जबाब देहन्दा अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य बेबुनियाद एवं मनगढन्त होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करते है। प्रार्थनापत्र के



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जयपुर

पद संख्या 7 का जबाब है कि जब सायलान् का वादग्रस्त सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं है तो सीमा विवाद करना उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करना आदि तथ्य झूठे बेबुनियाद है वादग्रस्त सम्पति में सायलान् का न तो राजस्व रेकॉर्ड में कभी नाम इन्द्राज रहा है न ही मौके पर कोई कब्जा काशत रहा है। वादग्रस्त सम्पति पर 1976 से जबाब देहन्दा के पिता का आवंटन सुदा भूमि पर कब्जा था और उसके बाद में वर्तमान समय में जबाब देहन्दा का कब्जा काशत है इसलिए सायलान् को उक्त सम्पति में कानूनन कोई हक अधिकार नहीं है इसलिए सायलान् द्वारा इस पद में वर्णित तथ्य बेबुनियाद एवं मनगढन्त होने से जबाब देहन्दा स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 8 का जबाब है कि समस्त तथ्यो परिस्थितियो दस्तावेजात मौके पर कब्जे काशत आधार पर प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से गैरसायलान् के पक्ष में बखुबी साबित है सायलान् का न तो राजस्व रेकॉर्ड में नाम है न ही मौके पर कब्जा है यदि सायलान् इस प्रार्थनापत्र की आड में जबाब देहन्दा की खातेदारी एवं कब्जे काशत की भूमि में कोई दखलन्दाजी करते हैं या बाधा अडचन पैदा करते हैं तो जबाब देहन्दा को भारी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है, इसलिए सायलान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सिणला की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 475 वक्त सैटलमेंट गै.मु. मगरी के रूप में दर्ज है। लेकिन इसका कुछ भाग काबिल काशत है जिस पर सायलान् के पिता छोगा व चुना तथा गैरसायल संख्या 01 से 04 के पिता रुघा का वक्त सैटलमेंट से कब्जा काशत है। लेकिन सैटलमेंट कर्मचारियो द्वारा मौके की बिना जांच किए केवल अप्रार्थीगण के पिता रुघा का नाम 1-15 बीघा भूमि नियमन/आवंटन कर दिया, जो कि गलत है। मौके पर उभयपक्ष के रहवासी मकान भी बने हुए हैं। अतः प्रार्थीगण 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता रुघाराम पुत्र गिगाराम को भूमिहीन होने से आवंटन/नियमन हुई थी जिसमें प्रार्थीगण का कोई अधिकार नहीं है।



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी नही होकर अप्रार्थीगण के पिता की सम्पति है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के अनुसार वादग्रस्त आराजी बीजाराम मांगीलाल झूमरलाल धोकलराम मदनलाल पि. रुघाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 के अंकन अनुसार नामान्तरण संख्या 209 द्वारा रुघा पुत्र गीगा का नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो से यह साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता रुघाराम पुत्र गिगाराम को आवंटित/नियमित भूमि है। तथा ऐसी भूमियां संबंधित आवंटी की स्वअर्जित भूमि मानी जाती है जिसे पैतृक पुश्तैनी आराजी नही कहा जा सकता है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होना नही माना जा सकता है अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्ण्य क्षति :- चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित हुआ है, साथ ही वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता रुघाराम पुत्र गिगाराम को आवंटन/नियमनशुदा है जो कि आवंटी की स्वार्जित सम्पति है, तथा ऐसी आराजी में प्रार्थीगण के पक्ष में कोई सुविधा का संतुलन होना या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने की दशा में प्रार्थीगण को अपूर्ण्य क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है लिहाजा उपर्युक्त दोनो बिन्दू भली भांति साबित नही होने से प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

:- आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपटित धारा 151 सीपीसी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भांति साबित नही होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित्त निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 28/07/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
(जिला-पाली)
जैतारण, जिला-पाली